श्री राधा किशन मालवीय : उपसभापति महोदया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इंदौर के लिए 2.76 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, रायपुर बिलासपुर, जबलपुर और ग्वालियर—ये बहुत बड़े-बड़े नगर हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन शहरों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार से कितने रुपए की सहायता की मांग कि और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को इन शहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि दी ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह तो स्टेट लोन है और उसके लिए सैंटर से कोई सैंट्रल असिस्टैंस नहीं है। लेकिन फिर भी जो 10 शहर हैं उनमें इंदौर की बात भी आई है। 24.10 अमेरिकन मिलियन डालर की जो बात है उसमें यह शहर भी कवर होते हैं। टेक्नीकली कुछ उसमें खामियां थीं जिसके लिए हमने स्टेट गवर्नमैंट को लिखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां की जो बेसिक नीड्स हैं वे इससे पूरी हो सकें।

167. [*The questioner (Shri D. B. Chandra Gowda) was absent. For answer, vide Col. 38-40 infra*].

*168. [*The questioners (Shri Lal K. Advani and Shri Ashwani Kumar) were absent.. For answer,* vide *Col* 40 infra]

Prompt Rehabilitation of Tribals

*169. SHRI B. L. PANWAR:†
SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been issued to the States to ensure prompt rehabilitation of tribals uprooted due to implementation of development projects in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is Government's view about widespread complaints that the funds sanctioned under various schemes are not reaching the beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): (a) and (b) Yes, Madam. The existing guidelines were issued in Feb., 86. Bureau of Public Enterprises in respect of land acquisition and rehabilitation aspects involved in major projects which apply to tribals also. Under these guidelines, rehabilitation will be monitored by Rehabilitation Cells to be set up by Project Authorities. The entire cost of rehabilitation will form a part of the project cost. Where the oustees are tribals, the guidelines further provide that the Ministry of Welfare and Ministry of Environment and Forests would be associated with the prepartion of the rehabilitation shcemes. On acquisition of land, these guidelines guard against indiscriminate acquisition in excess of actual requirements.

(c) Although Government has not received specific complaints regarding sanctioned funds not reaching the displaced tribals, the guidelines are under review to provide for adequate and effective rehabilitation and resettlement of tribals ousted by major projects.

श्री भंवर लाल पंवार : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में एक शब्द का प्रयोग किया है "विशिष्ट" और कहा है कि पुर्नवास के लिए स्वीकृत धनराशि विस्थापितों तक नहीं पहुंचने के संबंध में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। लेकिन यह वास्तविकता है और सत्य है और एक वकील के नाते मेरे पास फिगर्स भी हैं कि कहां-कहां हिन्दुस्तान में बांध की योजनाएं बनी हैं

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri B. L. Panwar.

और वहां से जिन लोगों को हटाया गया है उनको मुआवजे पूरे नहीं दिए गए हैं। यह 1986-87 की एन्यूअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री आफ वाटर रिसोर्सेज की। इसमें भी इस प्रकार की जो अलग राशि बांध के बनने के समय विस्थापितों को दी जानी थी उसका भी विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन यह तथ्य है कि कोई भी योजना बनने पर विस्थापितों के लिए अलग धनराशि निर्धारित की जाती है लेकिन इस जवाब में यह नहीं आया है कि जितनी भी योजनाएं बनी हैं ....

उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री भंवर लाल पंवार : मैं पूछना चाहूंगा कि इन योजनाओं में विस्थापितों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है उसका पूर्ण उपयोग भी हो चुका है या नहीं, यह बताएं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सदस्य ने यह कहा कि जितनी धनराशि दी गई है उसका उपयोग हुआ है या नहीं, यह वह जानना चाहते हैं। मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि कोई स्पेसिफिक ऐसी शिकायत एक जगह से या दो जगहों से नहीं आई है। लेकिन फिर भी वैलफेयर मिनिस्ट्री इस बात को देख रही है कि जो हमारे आदिवासी ऐसे प्रोजैक्टस के द्वारा चाहे व पुराने हैं या नए हैं, विस्थापित हैं, अपनी जगह से हटाये गये हैं उन्हें पूरी तरह से बसाया नहीं गया है या जो उन्हें कम्पनसेशन मिलनी चाहिए वह नहीं दी गयी है तो फिर से जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन्स हैं उनमें और क्या तबदीली की जा सकती है, किस तरह उसमें नया और जोड़ सकते हैं जिससे कि आदिवासी भाइयों को यह तकलीफ न हो और जो भी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वह अगर किसी खास प्रोजैक्ट के बारे में लिख कर भेजेंगे तो मैं उसकी जानकारी कर ...

श्री भंवर लाल पंवार : उपसभापति महोदया, विस्थापित किये गये व्यक्ति सीधे केन्द्र को अपनी शिकायत भेजें न तो यह सम्भव है और न होता है। इसके लिए प्रक्रिया यह हो सकती है कि या तो सम्बन्धित राज्य सरकारें इस प्रकार की स्टेटमेंट्स मंथली, क्वार्टरली, एनुअली मांगें और उसका कार्यान्वयन हो। तो क्या राज्य सरकारों में ऐसी कोई स्टेटमेंट मांगी है या केन्द्र ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं के संबंध में ऐसी कोई मंथली, क्वार्टरली या एनुअली स्टेटमेंट मांगकर यह जानकारी हासिल की है? नहीं की है तो इसके लिए क्या किया जा रहा है क्योंकि अभी तक इन विस्थापितों को मुआवजा नहीं दिया गया है?

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी : माननीया, जहां तक सवाल है क्वार्टरली रिपोर्ट का यह तो बड़े प्रोजैक्ट के साथ सभंव नहीं होता है। इसके लिए तो पूरी एक योजना बनाई जाती है। अभी जो गाइड लाइन है उसके अन्तर्गत भी कम्पनसेशन देने की बात है लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं जब कोई प्रोजैक्ट बनता है या कोई बांध बनता है या दूसरा कोई कार्यक्रम बनता है जिससे सीधा संबंध डवलपमेंट के साथ-साथ उनके हटने का हो जाता है तो जो अभी तक लैंड एक्वीजिशन एक्ट है उसमें केवल कैश न देने की बात होती है लेकिन साथ-साथ आदिवासियों के लिए यह जरूर कठिन होता है कि फिर वह कहां पर दूसरी जगह जायें। हमें यह सब मालूम रहता है और इसके लिए अब हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे इन आदिवासियों की परेशानियां दूर की जा सकती है। क्योंकि लैंड एक्वीजिशन एक्ट के लिए रिहेबिलिटेट प्वाइंट नहीं रहता लेकिन अभी हमारी वैलफेयर मिनिस्टरी उसको पूरी तरह से देख रही है।

SHRI KAPIL VERMA: The main source of sustenance of the tribals is forest and not land. Ninety per cent of their livelihood comes from

the forest produce. So, the principle of compensation based on land is not correct. Will the Government issue separate guidelines for deciding compensation in the light of the use of forest made by them. Secondly, will the compensation be determined on the basis of market value of the land and not on the basis of records, because when the tribals sell their land to the fellow-tribals, the price is very very low?

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: In the new guidelines which the Ministry has already prepared, all those defects which were there in the previous guidelines are being taken care of. They will remove all those anomalies and problems which we and the tribals are facing at present. These guidelines also take into consideration, all the points about the market value and other things which the hon. Member has just now raised.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: Madam Deputy Chairman, it is a fact that since inception of our independence big projects have been set up by the Government of India mainly in the tribal areas and the result is lakhs and lakhs of tribals are uprooted from their homes and hearths. There is no figure at all as to how many tribals have been rehabilitated in Bhilai, Rourkela and Ranchi where big projects have been set up. So, may I know from the Government whether they have figures of those people who have been uprooted up till now since independence? May I also know what process the Government is following in rehabilitating those people? Is it just giving them land for land? As some hon. Member has pointed out, they are not agriculturists but they are mostly dependent on forests. They are also human-beings. They are not intended to go to forests and serve there. I want the Minister to tell us and give us the figures they have collected for rehabilitation of those tribals?

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: Madam, Deputy Chairman, it is very difficult to say that since independence how many tribals have been uprooted or how many of them have not been rehabilitated. But in general we have got our guidelines about the rehabilitation and the rehabilition assistance will be limited to those whose lands have been acquired provided they are themselves cultivating those lands by residing in the home State. Absentee landlords will not be entitled to any rehabilitation assistance. So care has been taken with regard to these tribals who were living in those areas whose lands have been acquired and where projects have come up. Even rehabilitation part is also taken care of. Then persons whose land holdings have been completely acquired will be given priority for rehabilitation assistance as compared to others whose lands have been partially acquired. Madam, there are detailed guidelines about the rehabilitation of the Adivasis or Tribals. As I said earlier, all those defects which are existing in the guidelines will be removed; and these are under consideration of the Welfare Ministry.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : महोदया, मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में प्रश्न करना चाहती हूं । महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी उससे अफेक्ट हो रहे हैं । आप भी महाराष्ट्र की रहने वाली हैं ।

उपसभापति : बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन आप पूछ लीजिये ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : मैडम, हमारे वाटर रिसोर्सेज के मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं । आन्ध्र प्रदेश के अन्दर

एक भोपाल पट्टम प्रोजेक्ट बन रही है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मडारा डिस्ट्रिक्ट और गडचरौली डिस्ट्रिक्ट के कोई एक लाख आदिवासी अफक्ट होंग । बाबा आम्टे जी न भी इस बारे में हमारी पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी चर्चा की थी और यह सवाल उठाया था कि इन एक लाख आदिवासियों को बसाने के बारे में सरकार कोई निर्णय ले । इन आदिवासियों की जिन्दगी फोरेस्ट में गुजरी है । इसके अलावा यह फोरेस्ट सबसे बड़ा फोरेस्ट माना जाता है । यह सबसे ज्यादा डेन्स है और यहां पर जो टीक वुड मिलती है वह शायद सारे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलती है । इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने इन एक लाख आदिवासियों को बसाने के लिए क्या निर्णय लिया है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : माननीया, अभी हमारी जो पालिसी है आदिवासियों को बसाने के सिलसिले में वह यह है कि अब जब कहीं पर भी कोई प्रोजैक्ट बनेगा तो उसमें उनके रीहेबिलिटेशन की कास्ट इन्क्लूड की जायेगी और फिर वह प्रोजैक्ट सैंक्शन होगा । साथ ही साथ इसकी लीगल बांइडिंग भी हम करने जा रहे हैं । इस तरह से पिछले वर्षों में जो नहीं हुआ था अब उसको किया जा रहा है । इस तरह से अनिश्चिय भविष्य किसी आदिवासी का नहीं होने जा रहा है ।

SHRI DEBA PRASAD RAY: Madam, I believe that these issues have another dimesnion. (*Interruptions*).

The DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief. The time is very short.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Madam, I am on a point of order. I want to know as to what hour is going on, the Question Hour or something else?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Question Hour.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: But this is not related to the question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, he is asking a question.

SHRI DEBA PRASAD RAY: Madam, I believe that these problems have another dimension. Some of the major projects as, for example, Koelkaro in Bihar and Balco Project in Orissa, these are being delayed as far as the implementation part is concerned. (*Interrupions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please come to the question.

SHRI DEBA PRASAD RAY: Yes, I am coming to the question. The local tribals are feeling that the development is taking place at the cost of their interests. So, apart from providing rehabilitation to them, how do the Government propose to educate them to accept the development process and make them partners in the development process of the country.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: As far as Balco project is concerned, I think, the Government has taken proper precaution for the rehabilitation and when this project will be declared, the rehabilitation part will also be taken into consideration.

Use of Fertilizer for Making Explosives

*170. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Fertilizer being used to make explosives" as reported in the 'Indian Express', dated 2nd June, 1987;

(b) if so, whether it is a fact that the fertilizer; Calcium Ammonium (CAN) is bought by unscrupulous traders in the country and is being used to make explosives; and